

ऑटो और ड्रोन उद्योगों के लिये PLI योजना

प्रलिस के लिये

उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना

मेन्स के लिये

ऑटो और ड्रोन उद्योगों के लिये PLI योजना का महत्त्व और संबंधित चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की वनरिमाण क्षमताओं को बढ़ावा देने हेतु ऑटो, ऑटो-कंपोनेंट्स और ड्रोन उद्योगों के लिये 26,058 करोड़ रुपए की 'उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन' (PLI) योजना को मंजूरी दी है।

- ऑटो, ऑटो-कंपोनेंट्स और ड्रोन उद्योगों के लिये शुरू की गई 'उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन' योजना, केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान 13 क्षेत्रों के लिये घोषित PLI योजना का हिस्सा है, जसिमें 1.97 लाख करोड़ रुपए का परवियय शामिल है।
- यह 'आत्मनरिभरता' की दशा में भारत की यात्रा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है और भारत को ऑटो एवं ड्रोन नरिमाता देशों की शीर्ष सूची में शामिल करने में मददगार हो सकता है।

Takeaways

Auto



- Incentives worth ₹26,058 crore to be provided over five years
- To attract fresh investments of over ₹42,500 crore
- Incremental production of ₹2.3 lakh crore
- Job creation for 7.6 lakh people
- To help promote advance automotive technologies, clean energy
- Open to existing automotive companies and new investors

Drone

- Drone industry to be allocated ₹120 crore, over three years
- Expected to bring fresh investments of over ₹5,000 crore
- Incremental production of over ₹1,500 crore likely



प्रमुख बढि

HOW DOES THE INCENTIVE WORK

It is a kind of subsidy to the sector

Is a direct	Amount	Is based on
payment from the budget to goods made in India	varies from sector to sector	disadvantage /disability faced by a sector

■ 'उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन' योजना

- मार्च 2020 में शुरू की गई 'उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन' योजना का उद्देश्य घरेलू इकाइयों में नरिमिति उत्पादों की बढ़ती बिक्री पर कंपनियों को प्रोत्साहन देना है।
- विदेशी कंपनियों को भारत में इकाई की स्थापना के लिये आमंत्रित करने के अलावा इस योजना का उद्देश्य स्थानीय कंपनियों को मौजूदा वनिरिमाण इकाइयों की स्थापना या वसितार हेतु प्रोत्साहति करना भी है।
- इस योजना को [ऑटोमोबाइल](#), [फारमास्यूटिकलस](#), [आईटी हार्डवेयर](#) जैसे- लैपटॉप, मोबाइल फोन और [दूरसंचार उपकरण](#), व्हाइट गुड्स, रासायनिक सेल, [खाद्य प्रसंस्करण](#) एवं [वस्त्र उद्योग](#) आदि क्षेत्रों के लिये भी अनुमोदति कतिया गया है।

■ ऑटो सेक्टर के लिये PLI योजना

- इसमें पारंपरिक पेट्रोल, डीज़ल और CNG सेगमेंट (आंतरिक दहन इंजन) को शामिल नहीं कतिया गया है, क्योंकि भारत में इनकी पर्याप्त कृषमता मौजूद है।
- इसके तहत केवल एडवांस ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकियों या ऑटो घटकों को ही प्रोत्साहति कतिया जा रहा है, जनिकी आपूर्ति शृंखला भारत में कमज़ोर या नषिकरयि है।
- इसका उद्देश्य नई तकनीक और स्वच्छ ईंधन की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।

■ अवयव:

- चैपयिन मूल उपकरण नरिमाता (Original Equipment Manufacturers- OEM) योजना:
 - यह एक सेल्स वैल्यू लकिड प्लान है, जो सभी सेगमेंट के बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों और [हाइड्रोजन फयुल](#) सेल वाहनों पर लागू होता है।
- चैपयिन प्रोत्साहन योजना:
 - यह उन्नत प्रौद्योगिकी घटकों, कंपलीट-नॉकड डाउन (CKD) या सेमी-नॉकड डाउन (SKD) कटि, दोपहिया वाहनों, तीन पहिया वाहनों, यात्री वाहनों, वाणजियक वाहनों और ट्रैक्टरों के लिये बिक्री मूल्य से जुड़ी योजना है।

■ महत्त्व:

- [उन्नत रसायन बैटरी](#) (Advanced Chemistry Cell) के लिये पहले से शुरू की गई PLI और फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैनुफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकलस ([FAME](#)) योजना के साथ यह योजना भी [इलेक्ट्रिक वाहनों](#) के नरिमाण को बढ़ावा देगी।
- यह कार्बन उत्सर्जन और तेल आयात को कम करने में योगदान देगा।
- यह उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ऑटो घटकों के उत्पादन को प्रोत्साहति करेगा जो स्थानीयकरण, घरेलू वनिरिमाण को बढ़ावा देगा और विदेशी नविश को भी आकर्षति करेगा।
- यह नई सुविधाएँ स्थापति करने और अधिक रोज़गार सृजति करने में मदद करेगा। इससे ऑटो सेक्टर के लिये 7.5 लाख नौकरयि पैदा होने की उम्मीद है।

■ ड्रोन सेक्टर हेतु प्रोडक्शन-लकिड इंसेंटिवि (PLI) :

- परचिय :
 - इसमें एयरफ्रेम, प्रोपल्शन ससिस्टम, पावर ससिस्टम, बैटरी, इनरटयिल मेजरमेंट यूनिटि, फ्लाइट कंट्रोल मॉड्यूल, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, कम्युनिकेशन ससिस्टम, कैमरा, सेंसर, स्परेइंग ससिस्टम, इमरजेंसी रकिवरी ससिस्टम और ट्रैकर्स सहतिवभिन्न प्रकार के ड्रोन कंपोनेंटस शामिल हैं।
 - इससे 5,000 करोड रुपए से अधिक के नए नविश को बढ़ावा एवं 1,500 करोड रुपए से अधिक के वृद्धशील उत्पादन तथा लगभग 10,000 नौकरयि के अतरिकित रोज़गार सृजति होने की संभावना व्यक्त की गई है।
- महत्त्व :
 - यह उद्यमयिों को वैश्विक बाज़ार के लिये ड्रोन, घटकों और सॉफ्टवेयर के नरिमाण की दशिा में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहति करेगा। यह ड्रोन के अनुप्रयोग के लिये वभिन्न प्रकार के कार्यक्षेत्र भी खोलेगा।
 - इससे आयात कम करने में मदद मल्लिगी। वर्तमान में भारत में 90% ड्रोन आयातति है।
 - सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारत को वैश्विक ड्रोन का हब (केंद्र) बनाना है।

स्रोत : इंडियन एक्सप्रेस

